(d) No definite time limit can be indicated at this stage.

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने समय से इस प्रश्न पर विचार हो रहा है और इसमें इतनी देरी होने के विशेष कारण क्या हैं ?

डा० पं० श० देशमुख : एक वक्त हमारी मिनिस्ट्री का ऐसा ख्याल था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । इस पर फिर गौर किया गया और मैं ने भी आश्वासन दिया था कि हम इस बारे में कुछ और सोचेंगे उसके मुताबिक अभी फैसला हुआ है कि हम यह बोर्ड बनायेंगे ।

श्री भक्त दर्शन : यह बोर्ड जो बनाया जा रहा है यह निजी रूप से सीधे कार्य करेगा या जो राज्यों में इस प्रकार के बोर्ड पहले से बने हैं उनसे अपने काम में सहायता लेगा ?

डा० पं० श० देशमुख : हमारी मिनिस्ट्री के काफी काम तो सूबों की सरकारें ही करती हैं । जहां तक डाइरेक्ट (सीधे) काम करने का सवाल है, हम यह बोर्ड कोआर्डिनेशन (समन्वय) के लिये ही बना रहे हैं ।

Sugar Cane

*790. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of sugarcane crushed in the various sugar factories in different States and sugar recovered out of that during 1955-56 ;

(b) whether Government have formulated any scheme to export sugar from surplus to deficit areas in the country ; and

(c) if so, the period within which the scheme will be implemented ?

The Minister of Agriculture (Dr. P. S. Deshmukh) : (a) A statement giving the required information is laid on the table of the Lok Sabha. [*See* Appendix V, annexure No. 3.]

(b) No. The movement will be undertaken by the trade.

(c) Does not arise.

श्री विभूति मिश्र : इस स्टेटमेंट को देखने से पता चलता है कि सारे देश में गन्ने की ईल्ड में दस परसेंट से देसी चीनी हुई है और इस वजह से क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि किसान को जो तीन आने मन गन्ने की कीमत में मई के बाद नुकसान उठाना पड़ा है उसे कुछ प्रान्तीय सरकार के सेस (उपकर) से, कुछ केन्द्रीय सरकार की एक्साइज ड्यूटी (उत्पादन-शुल्क) से और कुछ मिल वालों के मुनाफे में से काट कर पूरा किया जाये ।

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री श० प्र० जैन) : ऐसा कोई विचार नहीं है कि एक्साइज ड्यूटी में से पैसा दिया जायेगा । जहां तक राज्यों के सेस का सम्बन्ध है, मेरी इत्तला है कि उनका भी कुछ देने का इरादा नहीं है । माननीय सदस्य को यह भी मालूम होना चाहिये कि जहां एक तारीख के बाद कीमत को रिकवरी (निकासी) से सम्बद्ध किया जाता है, तो जिस वक्त कीमतें ज्यादा होती हैं तो बोनस भी दिया जाता है ।

श्री विभूति मिश्र : जब ईल्ड कम होती है तब भी मिल वालों का मुनाफा उतना ही रहता है और सेस और एक्साइज ड्यूटी भी उतनी ही ली जाती है । केवल किसान को नुकसान होता है । क्या सरकार इस प्रश्न पर कुछ सोचेगी ?

श्री श० प्र० जैन : यह तो माननीय सदस्य ने एक बहस तलब बात उठाई है जिसके ऊपर यहां आध घंटे तक बहस भी हो चुकी है । उस समय जो मामला था वह मैंने साफ कर दिया था ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने गवर्नमेंट को लिखा है कि वह अपने सेस में से कुछ छोड़ने को तैयार है बशर्ते कि गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी में से भी कुछ छोड़ने को तैयार हो ताकि किसानों को जो ईल्ड की कमी की वजह से नुकसान हुआ है वह पूरा किया जा सके ।

श्री श० प्र० जैन : प्रान्तीय सरकारें हमको क्या लिखती हैं और हम उसके ऊपर क्या कार्यवाही करते हैं इसके सम्बन्ध में तो मैं

समझता हूं कि चर्चा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं यह भी बता दूं कि प्रान्तीय सरकार के पास से हमारे पास कोई ऐसी चिट्ठी आने वाले सीजन के बारे में नहीं आयी है।

Shri B. S. Murthy : Arising out of the question, may I know whether the Government have decided the areas and what steps are being taken to make them self-sufficient?

Shri A. P. Jain : We assess the sufficiency of the country as a whole not of the different areas. When granting licences we select more suitable areas and wherever sugar is needed we provide facilities for the transport from one part of the country to the other.

Shri Mohiuddin : May I know whether the Government has considered the possibility of adjusting the price in the early part of the season and the latter part of the season in such a way that when the yield of sugar-cane in the latter part of the season is less, the prices are so regulated that cultivators get the same price throughout the season?

Shri A. P. Jain : For the last few years the production of sugar-cane in the mill zones has been going up very rapidly. Probably, the cause for this rapid increase is the comparatively higher price of the sugar-cane that is being paid to the cane grower in the mill area. In fact we made some investigation and we found the price which the manufacturer of gur gets was 13 annas or 14 annas, the supplier to the sugar mills gets Rs. 1-7-0 or Rs. 1-5-0. The whole question is causing us a lot of.....

An hon. Member : Headache.

Shri A. P. Jain Headache and we are thinking of working out some scheme—maybe that zones may have to be re-adjusted, maybe that some restrictions on suppliers of certain types may have to be imposed so that the cane is properly crushed. My own idea—and I am very well supported by the experts—is that the cane should normally be crushed only during the optimum period when the recovery is the highest and it is uneconomical to crush it when the recovery goes down. We are trying to work out a scheme on these lines.

Shri Shivananjappa : May I know whether the price is being fixed on the basis of the recovery?

Shri A. P. Jain : We appointed a Committee and that Committee has made recommendations. Those recommendations are under examination. But I may frankly state that I have the largest amount of sympathy with the proposition that the price of sugar-cane should be correlated with the recovery.

Shri Ramachandra Reddi. : May I know whether there has been any definite improvement in the matter of the assistance and co-operation given by the Railway Department, in regard to the transport of sugar to the needy areas?

Shri A. P. Jain : There was never any dislocation, and we are having more and more of co-operation.

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार रिकवरी (प्रारित) पर जब कीमत देने की बात ठीक कर रही है तो उसके पहले सब किसानों की अच्छी क्वालिटी (किस्म) के शुगरकेन (गन्ना) का बीज सप्लाई कर सकेगी?

श्री अ० प्र० जैन : माननीय मेम्बर को यह मालूम होना चाहिए कि किसान को अच्छा बीज मुहैय्या करने के सम्बन्ध में जितना अच्छा काम गन्ने के सम्बन्ध में हुआ है उतना किसी दूसरी फसल के बारे में नहीं हुआ है और बराबर इस बात की कोशिश की जा रही है कि किसान को अच्छे से अच्छा बीज मिल सके और उन कोशिशों के फलस्वरूप जो गवर्नमेंट ने की हैं, गन्ने की पैदावार उत्तर प्रदेश और बिहार में ५० प्रतिशत अधिक बढ़ी है।

Food Production in the Second Plan Period

*792. **Shri H. N. Mukerjee :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the fact that in regard to the raising of food Production targets in the Second Five Year Plan, differing statements have been made lately by the Prime Minister, by himself, by the Minister of Agriculture, and by spokesmen of the Planning Commission ; and

(b) what, if any, is the agreed formulation?

The Minister of Agriculture (Dr. P. S. Deshmukh) : (a) It cannot be said that there is any basic contradiction between the views so far expressed on the question of raising the targets of agricultural production under the Second Five Year Plan as these views represent only tentative suggestions and not any final conclusions. In fact these suggestions constitute an essential part of the process of thinking connected with the formulation of the plan target.

(b) The matter is still under consideration.